THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): As per SRS estimate of Registrar General of India, the infant mortality rate shows a declining trend from 110 in 1981 to 104 in 1984. The steps taken by the Government to reduce infant mortality include expansion of existing health infrastructure, training of manpower, health education, adoption of risk approach, universal immunisation of children control of diarrhoel disease, prophylaxis against nutritional anaemia and supplementary nutrition under ICDS scheme.

Boycott of 13th Commonwealth Games at Edinburgh

*435. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has been asked to pay £ 2.45 lakh for having boycotted the 13th Commonwealth Games held in Edinburgh, in July, 1986;

(b) if so, what action has been taken by Government in the matter; and

(c) what are the names of the other countries which also boycotted the Commonwealth Games and have been asked to pay similarly?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF THE YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The Indian Olympic Association has indicated that it has not received any claims in this regard.

(b) Does not arise.

(c) The information sought concerns transactions among foreign Governments and is not available.

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव

†436. **श्री राम अवधेश सिंह :**
श्री शरद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने विश्वविद्यालयों में 1986–87 के शैक्षिक सत्र के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई और प्रत्येक मामले में यह कितने-कितने दिन के लिए लाग की गई ;

(ख) ऊपर उल्लिखित विश्वविद्यालयों में कितने छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा किन कारण से गिरफ्तार किया गया ?

(ग) किन-किन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कब से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विश्वविद्यालय परिसर में शांति रहे तथा पुलिस का प्रवेश कम से कम हो, इस के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करने वाले केवल नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं । इनमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय ने, जिन्होंने 1985 में अपना कार्य आरंभ किया, अभी तक किसी भी छात्र को दाखिल नहीं किया है । दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विश्व भारती तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय, में चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में गड़बड़ी की कुछ सूचनाएं मिली हैं । केवल अलीगढ़ मुस्लिम

विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने परिसर में गड़बड़ी के कारण 144 आई०पी०सी० लागू करने की सूचना दी । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्र किया जा रहा है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने गड़बड़ियों के कारण छात्र संघ का चुनाव इसके गठन की पुनःसंरचना होने तक नहीं कराने का निर्णय किया है ।

(घ) सामान्यतः परिसर में पुलिस हस्तक्षेप केवल तब ही आवश्यक होता है जब बड़ी घटनाएं होती हैं जिनमें या तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उनकी सहायता की मांग करते हैं या कानून और व्यवस्था प्राधिकारी शांति भंग होने की आशंका से उनका हस्तक्षेप आवश्यक समझते हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जो कि दोनों ही बड़े आवासीय विश्वविद्यालय हैं, के परिसरों में स्थानीय पुलिस की एक छोटी ईकाई तैनात की गई है ।

Sports schools and astro-turf grounds

*437. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the places where Government propose to set up Sports Schools in the country during the next five years; and

(b) what is the number of Astro-turf grounds proposed to be prepared for different sports during the ensuing five years in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Although there is no scheme under consideration of the Government of India for the setting up of sports schools as such in the country, some States have already set up sports schools and are supporting them. The Central Government has, however, in operation certain other schemes for spotting and nurturing of talent among students in the field of sports which are as under:

(i) The scheme of Sports Authority of India of adoption of schools for sports training.

(ii) The National Coaching Scheme implemented by the Netaji Subhas National Institute of Sports which operates 25 regional coaching centres in different States under the scheme.

(iii) The scheme of setting up of sports hostels in the country initiated by the Netaji Subhas National Institute of Sports.

(iv) The scheme of Sports Talent Search Scholarships of the Department implemented by the Netaji Subhas National Institute of Sports and the scheme of the National Sports Talent Contest of the Sports Authority of India.

(b) The approved scheme of laying of synthetic tracks and surfaces envisages sharing of expenditure on each synthetic track of surface between the State concerned and the Centre. The actual number of surfaces to be laid will, therefore, depend on the proposals that are made by the State Governments in the Seventh Five Year Plan is likely to be enough for the laying of twenty six surfaces.